POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2015/अंक 04

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अप्रेल, 2015 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राज्य विधान सभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वित्तमंत्री के रूप में वर्ष 2015-16 का बजट रखा। बजट में ग्रामीण स्तर तक शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य व स्वच्छता, जैसी बुनियादी जरूरतों को अहमियत दी गई है।

किसानों को जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाने, युवाओं को निजी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं रोजगार दिलाने, स्वयं सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, ग्रामीण विकास को तवज्जो देने और नागरिकों के हितों का खयाल रखने जैसे वादों को पूरा करने का भी बजट में सपना संजोया गया है।

पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने 'सुशासन कानून' लागू करने का जो वादा किया था, उसे फिर से इस बजट में दोहराया है। कुल मिलाकर बजट तभी अच्छा कहा जा सकेगा, जब घोषणाओं का समय पर सही क्रियान्वयन हो जाए। इसके लिए समय का निर्धारण और प्रशासनिक सुधार बेहद जरूरी है। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने भी लोकसभा में आम बजट प्रस्तुत किया। बजट में देश की आर्थिक सेहत को मजबूत बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' व निवेश के बल पर ग्रामीण विकास को पंख लगाने, आम उपभोक्ता को सशक्त बनाने तथा बुनियादी जरूरतों के साथ ही खेती और किसान के विकास को खास प्राथमिकता दी गई है। काले धन पर लगाम लगाने के प्रयास भी किए गए हैं।

बजट में कल्पना की गई है कि 2022 तक देश से गरीबी गायब हो जाएगी। जेटली का यह कहना कि हम गरीब और उद्योग-पतियों दोनों के पक्ष में हैं, मिडिल क्लास अपना ख्याल खुद रखे... यह क्या आम लोगों को अजीब सा नहीं लगा? कुल मिलाकर बजट में कई सुधार सामने आए हैं, जो देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने और बहुआयामी विकास को नई दिशा देंगे।

आम ग्रामीण बजट के आंकड़ों को सही रूप में समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता है, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर पैनी नजर रख सकें और लाभान्वित हो सकें।

किसानों को शून्य ब्याज पर ऋण

किसानों को कई बार खेती के लिए ऋण की जरूरत पड़ती है, लेकिन वे ऊंची ब्याज दर के डर से कर्ज नहीं ले पाते। मद्देनजर अब सरकार किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराएगी। राज्य भूमि विकास बैंक के माध्यम से दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों पर 5 फीसदी ब्याज अनुदान देने की योजना को इस बजट में भी लागू रखा गया है।

राज्य के पश्चिमोत्तर जिलों में जैतून की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को 200 हेक्टेयर क्षेत्र में जैतून के पौधारोपण के लिए अधिकतम 48 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। नागौर जिले में नया कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा। सिंचाई सुविधाओं का भी अतिरिक्त विस्तार किया जाएगा।

जैविक खेती को प्रोत्साहन

प्रदेश के बजट में खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। सरकार का प्रयास है कि खेती में केमिकल का कम से कम प्रयोग किया जाए। इसके लिए जैविक खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रदेश में जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन किसानों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

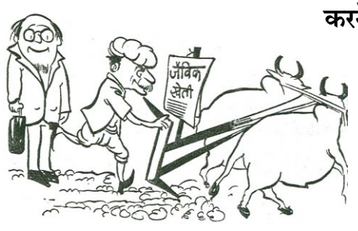

साथ ही चयनित किसानों को नवीन कृषि तकनीक की जानकारी के लिए देश-विदेश में भ्रमण कराने की योजना भी है। राज्य बीज निगम गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन करेगा और किसानों को उचित दर पर उपलब्ध कराएगा। बीजों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा शीघ्र ही ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने 18 मार्च को दिल्ली में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार में इस आशय का पत्र 'कट्स' प्रतिनिधि को प्रदान किया है। केन्द्र का शुभारम्भ अप्रेल, 2015 में उचित समय पर किया जाना है।

ग्रामीण विकास पर फोकस

केन्द्रीय व राज्य बजट में इस बार गांवों में रहने वालों की तरक्की और उनकी बुनियादी जरूरतों पर खास ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फ्लेगशिप योजना 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' की तर्ज पर मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की जा रही है। हर साल प्रत्येक विधायक एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकेगा इसकी गाइड लाइन जारी की जा चुकी है। निचले स्तर तक स्वास्थ्य इकाइयों को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ा गया है। इसके लिए एएनएम को पीसी टेबलेट दिए जाएंगे।

भवनविहीन पंचायतों में भवन बनवाने, व अच्छा काम करने वाली ग्राम पंचायतों से लेकर जिला परिषदों तक को सम्मानित किया जाएगा।

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केन्द्रों पर माइक्रो एटीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा मुहैया कराने के साथ ही ई-मित्रों को अब 40 के बजाय 107 सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। यह ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाने की मजबूरी से बचाएंगे।

मनरेगा में पक्के कार्य के लिए 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कोष बनेगा तथा 4110 गांवों में शौचालय बनवाने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य का पलड़ा-नब्ज पर हाथ

प्रदेश में आमजन को हैल्थ केयर की सुविधा देने के लिए आरोग्य राजस्थान अभियान के तहत पंचायतवार शिविर आयोजित करते हुए स्वास्थ्य की जांच कर, उसे भामाशाह योजना से जोड़ते हुए हैल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य संबंधी हैल्थ इंफोर्मेशन नेटवर्क तैयार हो सकेगा। इस डाटाबेस के आधार पर गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज हो सकेगा।

नए अस्पतालों व स्वास्थ्य केन्द्रों के विस्तार के लिए जिलेवार बजट आंवटित किया गया है। मुफ्त दवा और जांच योजना को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के साथ-साथ स्वास्थ्य बीमा और गांवों में निजी अस्पतालों के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चलाने के लिए 'रन ए पीएचसी' योजना लागू की जाएगी। किशोरियों की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेष योजना बनेगी।

गांव-गांव में आदर्श स्कूल

अब हर ग्राम पंचायत में एक विद्यालय को सरकार आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेगी। इससे हर दूर-दराज के गांवों तक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी। प्रदेश की 675 ग्राम पंचायतों के स्कूल 12 वीं कक्षा तक होंगे।

शिक्षा की निगरानी के लिए हर जिले में स्कूली शिक्षा के लिए एक जिला स्तरीय बोर्ड होगा।

खास बात यह है कि इस बोर्ड में अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। बोर्ड हर साल शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी कर अपनी रिपोर्ट देगा।

सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा की जिन छात्राओं के परीक्षा में 75 फीसदी से अधिक अंक आएंगे, उन्हें कॉलेज में प्रवेश लेने पर सरकार की ओर से प्रत्येक जिले की प्रथम 50 छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। छात्राओं के लिए बनी साइकिल योजना को लागू रखा गया है।

महिला एवं बाल विकास पर ध्यान

प्रदेश के 53 लाख 21 हजार बच्चों व महिलाओं के पोषाहार के लिए 1599 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दस जिलों में नवजात शिशुओं को दूध के लिए मदर्स मिल्क बैंक खोले जाएंगे। प्रदेश में 901 नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएंगें।

स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिला स्वावलम्बन को बढ़ावा देने के मकसद से 15 हजार नये स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 2 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 95 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है।

सरकार बालिकाओं के लिए 'सेल्फ डिफेंस' की योजना राज्य के सभी जिलों में लागू करेगी, जो बेटियों को स्व-रक्षा के उपायों से सुरक्षित बनाएगा। महिलाओं के लिए लर्निंग व वाहन चालक लाइसेंस बनवाने के लिए शुल्क में 50 फीसदी छूट दी गई है।

विकसित होगा विद्युत वितरण तंत्र

राज्य के बजट में ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ और विकसित करने के लिए कई घोषणाएं की गई है। वर्ष 2015-16 में 220 केवी व 632 केवी के 16 ग्रिड नए सब स्टेशन, 14 हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा और 26 हजार मेगावॉट के सोलर पॉर्क स्थापित किए जाएंगे। बजट में किसानों को 40 हजार कृषि कनेक्शन जारी किए जाने का भी प्रावधान है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 816 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, हनुमानगढ़ व बाड़मेर जिले में 1864 ढाणियों का विद्युतीकरण कर करीब 5 लाख 40 हजार विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे।

बजट में पिछले दिनों बिजली मंहगी होने से पड़े बोझ को कम करने के लिए सीएफएल, एलईडी बल्ब व ट्यूबलाइट पर टैक्स कम कर राहत देने की बात कही गई है।

सुधरेगी पीने के पानी की गुणवत्ता

बजट में जिलों की पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं पर खासा जोर दिया गया है। प्रदेश की 12 पेयजल योजनाओं पर 464 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा 23267 गांव-ढाणियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दो हजार आरओ प्लांट लगाए जाएंगे।

करीब दस करोड़ रुपए हैण्डपंपों को सुधारने पर खर्च होगा। पीने के पानी में फ्लोराइड की समस्या को दूर किया जाएगा। प्रदेश में बन्द जनता जल योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। इस पर करीब 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक हजार सोलर एनर्जी बेस्ड बोरवैल की स्थापना में 40 करोड़ रुपया खर्च होगा।

कमजोर वर्ग को सम्बल

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीडित परिवारों को समय पर मुआवजा तय करने और पूरी निगाह रखने के मकसद से योजना बनेगी तथा उसे भामाशाह योजना से जोड़ा जाएगा।

जनजाति उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्रों के मां-बाड़ी डे केयर सेंटरों में पोषाहार तैयार करने के लिए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। तीन हजार बीपीएल परिवारों को आवास निर्माण के लिए 21 करोड़ रुपए अनुदान का प्रावधान है।

किसानों को मिली राहत

प्रदेश में बेमौसम बरसात और ओले पड़ने से किसानों की खड़ी फसल तबाह हो गई। गेहूं व सरसों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। छोटे किसान पहले से ही कर्ज में डूबे हैं, इस विपदा ने उनकी सभी आशाओं पर पानी फेर दिया। ऐसे समय में उन्हें तुरन्त मदद मिलनी चाहिए।

हालांकि राज्य सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान करते हुए केन्द्र सरकार से भी विशेष पैकेज मिलने का भरोसा दिया है। चार माह के बिजली बिल माफ करने, आबियाना शुल्क नहीं लेने व जन-पशुधन हानि पर मुआवजा राशि को बढ़ाया है। प्राकृतिक आपदा में किसानों को तुरन्त मदद के लिए 'किसान सुरक्षा कोष' बनाया जाना चाहिए, जिसमें सरकार व जनता का योगदान हो।

-नानग राम बागड़ा, सीकर

बिजली ने मारा करंट

'ग्राम गदर' में बिजली चोरी रोकने के लिए बने कानूनों की जानकारी मिली। इससे बिजली चोरी पर रोक लगेगी। हाल ही बिजली महंगी होने से सभी के घर का बजट गड़बड़ा गया है। बिजली छीजत व विद्युत चोरी पर विद्युत वितरण कंपनियां लगाम नहीं लगा पा रही। इस विफलता का हर बार दण्ड आम उपभोक्ता भुगतता है।

अब उसके पास यही चारा है कि वह बिजली की बचत कर घर का बजट संभाले। वह एलईडी, सीएफएल और ट्यूब लाइट के उपयोग से कुछ खर्च कम कर सकता है। शहरों में सड़कों पर लगी लाईटें दिन में भी जलती देखकर दुःख होता है। बिजली के इस अपव्यय को कौन रोके? जबकि इस अपव्यय का पैसा आम जनता की जेब से जा रहा है।

- सीमा चतुर्वेदी, जयपुर

गांव-गांव में सड़कों का विस्तार

राज्य सरकार ने गांवों में सड़कों की समस्या को दूर करने के लिए ग्रामीण गौरव पथ योजना लागू की थी। इस बार इस योजना के तहत सड़कों के विस्तार और मरम्मत पर 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बताया कि प्रथम चरण में 2 हजार 154 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 2 हजार 119 किलोमीटर लंबाई की आरसीसी रोड व नाली निर्माण का काम प्रगति पर है।

इसके साथ ही गांवों को आपस में जोड़ने के लिए वर्ष 2015-16 में दो हजार किलोमीटर लंबाई की मिसिंग लिंक्स सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा।

लघु उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

कुछ सालों से मझोले व लघु उद्योगों पर ध्यान कम दिया जाने लगा था। इस बार सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार की है, जो इन उद्योगों के उत्पादों की प्राथमिकता आधारित कीमत तय करेगी। खादी को नया रंग-रूप दिया जाएगा।

खादी के लिए बाजार खड़ा करने और इससे जुड़े उत्पादों की डिजाइन के विकास और मार्केटिंग में सहायता के लिए 2.50 करोड़ रुपए का बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर